



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2965]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2018/श्रावण 9, 1940

No. 2965]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2018/SHRAVANA 9, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

का.आ. 3755(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि 'ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और ऐसी अन्य) का प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण' सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 29 के द्वारा सम्मिलित किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "लोक उपयोगी सेवाएं" घोषित किया जाना चाहिए;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "लोक उपयोगी सेवा" घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2017-आई.आर. (पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2018

S.O.3755(E).— Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the service in the **Processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like)** which is covered by item 29 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a "public utility service" for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a "public utility service" for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of publication of this notification.

[F. No. S.11017/ 2 / 2017 –IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.